Closure of J. K. Cotton Manufacturing Company, Kanpur

5332. SHRI UGRASEN: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the J. K. Cotton Manufacturer Company, Kanpur (U.P.) has been lying closed for the last one year, three thousand workers have been rendered jobless and are on the verge of starvation and have not been paid their wages and dues on account of gratuity, bonus, pay-off; and if so, the reasons therefor;

(b) whether Government will take over and arrange its normal functioning through National Textile Corporation; and

(c) the amount of taxes of the Central and State Government outstanding against the company and details in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) The J. K. Cotton Manufacturing Company, Kanpur has been lying closed since 1-10-1976 rendering about 2276 workers idle and causing hardship to them. The closure, is due to financial difficulties. It is despite State Government's refusal to grant the requisite permission. The management is taking the stand that the mill has not been formally closed but only production has been suspended. The Labour Commissioner has launched prosecution against the management for illegal closure. The monthly wage bill in this mill is reported to be of the order of Rs. 9 lakhs, but the management has not paid wages to the workers since the mill's closure except to the extent of Rs. 1.5 lakhs which were disbursed under pressure from State authorities. Bonus to the extent of Rs. 12 lakhs also remains unpaid. Action for ensuring payment of these dues is for the State authorities to take.

(b) As NTC is already shouldering heavy burden of managing 105 textile mills, Government is not in favour of taking more textile mills for management by the Corporation. However, if viable proposal for re-opening of the mills under the management of the State Government is received, the Central Government would extend all possible assistance.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Project Allowance

5333. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether project allowance is being paid to all the categories of employees in Ankleshwar such as bank employees, P. & T. employees, ONGC employees, CPWD employees, etc.;

(b) whether it is a fact that certain categories are still not getting the project allowance; and

(c) if so, the names of such categories and the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

राजस्थान में सहकारी योजनायें

5334. श्री श्याम सुन्दर सोमानी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने राजस्थान में विभिन्न सहकारी योजनाओं में कितनी धनराशि लगाई; और

(ख) योजनाओं की मुख्य बात क्या है तथा ये योजनायें कहां-कहां चालू की गई हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सह-कारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना का नाम	पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की राशि (रुपये लाख में)	योजना की मुख्य बातें	स्थान, जहां योजनाएं शुरू की गई हैं
1	2	3	4
(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं			
1. उर्वरकों आदि के वितरण के लिए उपान्त धन	10.00 (1974-75) 23.27 (1975-76) शून्य (1976-77)	राज्य क्षेत्रीय स्तर के विपणन संघों के विपणन तथा वितरण कार्यों के विस्तार एवं सुधार के लिए	यह योजना राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, जयपुर द्वारा चलाई जा रही है।
2. उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास	(1) 6.82 पिछले तीन वर्षों में	विकास की सम्भाव्यता रखने वाली उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका निभा सकें।	इस सहायता का उपयोग उदयपुर तथा अजमेर में बहु विभागी भंडार स्थापित करने तथा 7 चुनी उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के व्यापार का विस्तार के लिए किया गया।
	(2) शून्य (1974-75) 12.03 (1975-76) शून्य (1976-77)	सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित कपड़े का व्यापार करने के लिए उपान्त धन की सहायता हेतु, ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें।	जयपुर में राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ तथा 36 दूसरी सह समितियां, जिनमें राज्य के विभिन्न भागों में स्थित थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार तथा सहकारी विपणन समितियां शामिल हैं।

1	2	3	4
(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
1. केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के लिए सहायता	2.00 (1974-75) 2.39 (1975-76)	(i) सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्य में सहकारी शिक्षा के कार्य को तेज करने के लिए ।	(i) जयपुर तथा उदयपुर
		(ii) सहकारी कालिजों के माध्यम से सहकारी प्रशिक्षण ।	(ii) कोटा
	4.02 (1976-77)	(iii) **विशेष योजना**	
		(क) वर्तमान कनिष्ठ स्तर के केन्द्रों को मजबूत करना ।	(iii) (क) भरतपुर।
		(ख) कनिष्ठ प्रशिक्षण केंद्रों और सहकारी प्रशिक्षण कालिजों में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार प्रतिनियुक्त करने वाली कमजोर संस्थाओं को सरकारी आर्थिक सहायता ।	(ख) कोटा, जयपुर, जोधपुर तथा भरतपुर।
2. अल्प विकसित राज्यों में सहकारी विपणन, संसाधन और भण्डारण कार्यक्रमों के लिए सहायता ।	14.93 (1974-75)	(i) सहकारी विपणन समितियों के अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि उनको व्यापारिक गतिविधियों में सुधार तथा विस्तार हो सके ।	यह योजना राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनेक प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।
	48.40 (1975-76)	(ii) ढुलाई वाहन खरीदने के लिए विपणन तथा प्रोसेसिंग समितियों को सहायता ।	डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में 2 समितियों को सहायता दी गई ।
	79.70 (1976-77)	(iii) कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिटों तथा कपास ओटाई तथा प्रेसिंग यूनिटों, पशुचारा संयंत्रों आदि की स्थापना के लिए सहकारी कृषि प्रोसेसिंग योजनाएं ।	बिलारा, भीलवाड़ा, कोटा अन्त, अनूपगढ़, गजसिंहपुर, श्री गंगानगर, बूंदी तथा बरोदिया ।

1	2	3	4
		(iv) सहकारी भण्डारण योजना, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार विपणन तथा प्रोसेसिंग समितियों द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए सहायता दे रही है।	विभिन्न समितियां द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की गई।
		(v) सहकारी शीत भंडारण योजना उत्पादकों को आधिक्य के मौसम में अपनी खरीद को जमा करने और कमी के मौसम में उसे बेचने के लिए सक्षम बनानी है।	कोटा में केवल एक यूनिट।
		(vi) सहकारी डेरी योजना छोटे तथा मध्यम पैमाने के डेरी प्रोसेसिंग संयन्त्र तथा मिल्क चिलिंग केन्द्र लगाने के लिए है।	भीलवाड़ा अजमेर तथा जोधपुर।
3. सहकारी कताई मिलों की अंश पूंजी में भाग लेना।	6.25 (1974-75) 31.25 (1975-76) शून्य (1976-77)	कताई मिलों को अंश पंजी में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों की निधियों की अनुपूर्ति के लिए।	गुलाबपुरा और गंगानगर।

Indianisation of Foreign Tea Companies

3035. SHRI SHANKARSINHJI VAGHELA:

SHRI ANANT DAVE:

Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) the number and names of sterling tea companies operating in India;

(b) how far they have complied with the provisions of the FERA for Indianisation so far; and

(c) what was the time limit fixed and the number of times the date was extended and the final date fixed now?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). A statement is attached showing the details of Tea companies which had submitted